

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: IMF

प्रलिस के लयः

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबलिटी रपॉर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ।

मेन्स के लयः

महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, भारत के हतों, वकिस और संवृद्धिपर देशों की नीतयों और राजनीतिका प्रभाव, वश्व आर्थक आउटलुक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ।

चर्चा में कयों?

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, 2022 का नवीनतम संस्करण जारी कया ।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की मुख्य वशेषताएँ:

- **भारतीय परदृश्यः**
 - इसने वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धिको अप्रैल 2022 में शुरू हुए वत्तीय वर्ष के अनुमानति 7.4% के पूरवानुमान से घटाकर 6.8% कर दया है ।
 - इसके वर्ष 2023 में भारत की संवृद्धिदर का 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है । ।
- **वैश्वक परदृश्यः**
 - वैश्वक संवृद्धि में वर्ष 2021 के 6% से वर्ष 2022 में 3.2% और वर्ष 2023 में 2.7% तक कमी होने का अनुमान है । वैश्वक वत्तीय संकट और कोवडि-19 महामारी की चरम अवस्था को छोड़कर यह 2001 के बाद से सबसे कम संवृद्धिदर है ।
 - वर्ष 2023 में वैश्वक संवृद्धि और धीमी होने की संभावना है । इसके अनुसार सबसे अभी और खराब स्थति आ सकती है तथा कई लोगों के लयि वर्ष 2023 मंदी का होगा ।
 - वर्ष 2023 में यूरो कषेत्र में मंदी के और भी गहराने की आशंका है तथा चीन में कोरोनावायरस प्रकोप की शुरुआत के साथ दशकों के बाद सबसे कम संवृद्धिदर रहने का अनुमान है ।
- **मुद्रास्फीतिः**
 - वैश्वक मुद्रास्फीतिवर्ष 2021 के 4.7% से बढ़कर वर्ष 2022 में 8.8% होने का अनुमान है लेकिन इसके वर्ष 2023 में 6.5% और वर्ष 2024 तक घटकर 4.1% होने का अनुमान है ।
 - वैश्वक आर्थक गतविधि में मंदी, अधिक व्यापक और अपेक्षा से अधिक तीव्र है एवं मुद्रास्फीति भी दशकों के अनुभव से अधिक है । आर्थक परदृश्य मौद्रक तथा राजकोषीय नीतयों के सफल समन्वय, यूकरेन में युद्ध की स्थति और चीन में वकिस की संभावनाओं पर नरिभर है ।

GDP projections by IMF

World Economic Outlook released today shows Indian economy to grow at 6.8%, lower than it previous projection of 7.4%

Countries	2022	2023
India	6.8%	6.1%
Spain	4.3%	1.2%
UK	3.6%	0.3%
Canada	3.3%	1.5%
Italy	3.2%	-0.2%
China	3.2%	4.4%
Euro Area	3.1%	0.5%
Brazil	2.8%	1.0%
France	2.5%	0.7%
Mexico	2.1%	1.2%
Japan	1.7%	1.6%
US	1.6%	1.0%
Germany	1.5%	-0.3%

IMF के सुझाव:

- **मुद्रास्फीति को सीमित करना:**
 - मुद्रास्फीति से निपटने, केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट को संतुलित बनाने और वास्तविक नीति दरों को उनके तटस्थ स्तर से तेज़ी से ऊपर उठाने को प्राथमिकता देने के साथ दीर्घकाल में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना चाहिये।
- **मौद्रिक और राजकोषीय नीति समन्वय:**
 - अर्थव्यवस्थाओं में मांग को बढ़ाने के साथ अतिरिक्त सकल मांग सृजित करने और श्रम बाजारों को मजबूत करने में राजकोषीय नीति द्वारा मौद्रिक नीति का समर्थन करने की आवश्यकता है।
 - मूल्य स्थिरता के बिना जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि से भविष्य में होने वाली संवृद्धि के निरर्थक होने का खतरा है।
 - केंद्रीय बैंकों को अपने उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के प्रयासों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए दृढ़ता से इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।
- **समायोजन के दौरान कमज़ोर लोगों की रक्षा करना:**
 - जैसा कि जीवन यापन की लागत बढ़ती जा रही है, नीति निर्माताओं को उच्च कीमतों के प्रभाव से समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी।
- **जलवायु नीतियाँ:**
 - त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई के बिना जलवायु परिवर्तन का अंततः दुनिया भर में स्वास्थ्य और आर्थिक परिणामों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
 - वर्तमान वैश्विक लक्ष्य वैश्विक तापमान लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दशक के अंत तक उत्सर्जन में कम-से-कम 25% की कटौती की आवश्यकता होगी।
 - चल रहे ऊर्जा संकट ने ऊर्जा सुरक्षा लाभों को भी उजागर किया है, अतः देश अक्षय और कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों के साथ जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों में स्थानांतरित कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष:

- **परिचय:**
 - द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद युद्ध में तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये **वैश्व बैंक** के साथ **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष** की स्थापना की गई।
 - अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी। इसलिये इन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ संतानों यानी ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में भी जाना जाता है।
 - **IMF की स्थापना 1945** में हुई थी, यह उन 189 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। भारत ने 27

दिसंबर, 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की।

- IMF का प्राथमिक उद्देश्य **अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता** सुनिश्चित करना है, यह वनियम दरों और अंतरराष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों (और उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।
 - वर्ष 2012 में एक कोष के जनादेश के अंतर्गत वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करने के लिये इसको अद्यतित किया गया।

■ **IMF की रिपोर्ट:**

- **वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट**।
- **वरल्ड इकोनॉमिक आउटलुक**।

■ **वरल्ड इकोनॉमिक आउटलुक**

- यह IMF का एक सर्वेक्षण है जिसमें आमतौर पर वर्ष में दो बार- अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में प्रकाशित किया जाता है।
- यह नफिट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है।
- पूर्वानुमान के अपडेट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए वरल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी और जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल व अक्टूबर में प्रकाशित होने वाली मुख्य WEO रिपोर्ट्स के बीच का समय है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: “त्वरति वित्तीय प्रपत्र” (Rapid Financing Instrument) और “त्वरति ऋण सुविधा” (Rapid Credit Facility), नमिनलखिति में कसि एक के द्वारा उधार दयि जाने के उपबंधों से संबंधित हैं?

- (a) एशियाई विकास बैंक
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल
- (d) विश्व बैंक

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **त्वरति वित्तीय प्रपत्र (Rapid Financing Instrument-RFI)** त्वरति वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो भुगतान संतुलन आवश्यकताओं के तत्काल संतुलन का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिये उपलब्ध है। सदस्य देशों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिये IMF वित्तीय सहायता को और अधिक लचीला बनाने के लिये RFI को व्यापक सुधार के हिससे के रूप में बनाया गया था। RFI, IMF की पछिली आपातकालीन सहायता नीति की जगह लेता है और इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है।
- **त्वरति ऋण सुविधा (Rapid Credit Facility-RCF)** कम आय वाले देशों (low-income countries-LICs) को तत्काल भुगतान संतुलन (BoP) की आवश्यकताएँ प्रदान करती है, जहाँ कोई शर्त नहीं होती है और इस क्रम में एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम न तो आवश्यक है तथा न ही संभव। RCF की स्थापना एक व्यापक सुधार के हिससे के रूप में की गई थी ताकि वित्तीय सहायता को अधिक लचीला संकट के समय LICs की विविध आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके।
- **RCF के तहत तीन क्षेत्र हैं:** (i) घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति जैसे स्रोतों की एक विसृत शृंखला के कारण तत्काल BoP ज़रूरतों के लिये एक "नियमति खड़की" (ii) अचानक, बहर्जात झटके के कारण तत्काल BoP ज़रूरतों के लिये, एक "एक्सोजेनस शॉक वडि" और (iii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण तत्काल BoP ज़रूरतों के लिये एक "बड़ी प्राकृतिक आपदा खड़की" जहाँ कर्षता सिकल घरेलू उत्पाद के 20% के बराबर या उससे अधिक होने का अनुमान है।

Q. “स्वर्ण ट्रान्श” (रज़िर्व ट्रान्श) नरिदषिट करता है: (2020)

- (a) विश्व बैंक की एक ऋण व्यवस्था
- (b) केंद्रीय बैंक की कसि एक क्रयि को
- (c) WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को
- (d) IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को

उत्तर: (d)

Q. 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (2016) कसिके द्वारा तैयार की जाती है?

- (a) यूरोपीय केंद्रीय बैंक
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतरराष्ट्रीय बैंक
- (d) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

उत्तर: (b)

प्रश्न: वशिव बैंक और IMF, जनिहें सामूहकि रूप से बरेटन वुड्स को जुडवाँ संस्था के रूप में जाना जाता है, वशिव की आर्थकि एवं वत्तितीय व्यवस्था की संरचना का समर्थन करने वाले दो अंतर-सरकारी स्तंभ हैं। वशिव बैंक और IMF कई सामान्य वशिषताओं को परदर्शति करते हैं, फरि भी उनकी भूमकि, कार्य और अधदिश स्पष्ट रूप से भनिन हैं। व्याख्या कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2013)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-economic-outlook-imf-4>

